



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082023-248159
CG-DL-E-17082023-248159

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3520]
No. 3520]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2023/श्रावण 26, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2023/SHRAVANA 26, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2023

का.आ. 3679(अ).—जबकि मेसर्स रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 138, अंसल चैम्बर्स -II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 है, ने "मैसर्स रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड" के 300 MW हाइब्रिड उत्पादन परियोजना (विंड: 300MW, सोलर: 75MW, एवं स्टोरेज: 150 MWh, कोप्पल, कर्नाटक को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण योजना" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/19919/2022 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा "मैसर्स रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड" के 300 मेगावाट हाइब्रिड उत्पादन परियोजना, कोप्पल, कर्नाटक को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण योजना" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मेसर्स रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड ने 27.05.2022 (राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रजा वाणी, और संयुक्त कर्नाटक) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 09.07.2022 से 15.07.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स रिन्यू सूर्या ओजस

प्राइवेट लिमिटेड ने 21.06.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "मैसर्स रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट हाइब्रिड उत्पादन परियोजना, कोप्पल, कर्नाटक को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण योजना" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

"रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड जनरेशन स्विचयार्ड (टोंडीहाला गांव, कोप्पल ज़िला, कर्नाटक) - कोप्पल पी.एस. 220 के.वी डी/सी टावर पर एस/सी लाईन"

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

क्रम संख्या	गांवों के नाम	तालुक	ज़िला	राज्य
1	ताडाकल, तालाबल, तालाकल्ला, चित्तापुरा, कोमलापुरा, तालाबाला	कुकानुरा	कोप्पल	कर्नाटक
2	अडावल्ली, अडाविहाली, बन्नीकोप्पा, लिंगापुरा, मन्ननापुरा, इटागी, मंडलगिरि, मालीकोप्पा, सोमपुरा, शिडनीकोप्पा, बटाप्पनाहाली, चिक्कीनाकोप्पा, बिन्नाला, हीरे हानचिहल, टोंडेहल, टोंडीहाला, बण्डीहल, बण्डीहाला, रायनाहाला	येलबुर्गा		

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाईनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निवंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाईनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाईनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाईनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाईनों का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

- vi. मेसर्स रिन्यू सूर्या ओजस प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है। आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है।

[फा. सं. 25-16/10/2023-पीजी]

दीपक राव, निदेशक

**MINISTRY OF POWER
ORDER**

New Delhi, the 16th August, 2023

S.O. 3679(E).—Whereas M/s ReNew Surya Ojas Private Limited, the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under “Transmission scheme for providing connectivity to ReNew Surya Ojas Private Limited for its 300 MW Hybrid generation project (Wind:300 MW, Solar:75 MW & Storage:150 MWh) in Koppal, Karnataka”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. I/19919/2022 dated 19.01.2022 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s ReNew Surya Ojas Private Limited for the overhead lines covered under “Transmission scheme for providing connectivity to ReNew Surya Ojas Private Limited for its 300 MW Hybrid generation project in Koppal, Karnataka”.

M/s ReNew Surya Ojas Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers dated 27.05.2022 (Rajasthan Patrika, The Times of India, Praja Vani, and Samyukta Karnataka) and in Weekly Gazette of India dated 09.07.2022 to 15.07.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s ReNew Surya Ojas Private Limited has submitted an affidavit dated 21.06.2023 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under “Transmission scheme for providing connectivity to ReNew Surya Ojas Private Limited for its 300 MW Hybrid generation project in Koppal, Karnataka”. The following overhead lines are covered under this transmission scheme:

“ReNew Surya Ojas Private Limited generation switchyard (Thondihala village, Koppal District, Karnataka)- Koppal PS 220 kV S/C line on D/C towers.”

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

Sl. No.	Village	Tehsil	District	State
1	Tadakal, Talabal, Talakkala, Chittapura, Komalapura, Talabala,	Kukanura	Koppal	Karnataka
2	Adavalli, Adavihalli, Bannikoppa, Lingapura, Mannapura, Itagi, Mandalgeri, Malekoppa, Sompura, Shidnekoppa, Batappanahalli, Chikkenakoppa, Binnala, Hire Hanchehal, Tondehal, Tondihala, Bandehal, Bandihala, Rayana Hala	Yelburga		

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ReNew Surya Ojas Private Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and

posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- i. The approval is granted for 25 years;
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s ReNew Surya Ojas Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) potential area (or priority area) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and/or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/10/2023-PG]

DEEPAK RAO, Director